

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

फिर मुंबई शर्मसार!

35 साल के दरिंदे ने पड़ोस की 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किया रेप



मुंबई : महाराष्ट्र और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से मिली एक सनसनीखेज खबर के अनुसार, यहां के मानखुर्द इलाके से एक छह साल की बच्ची का बलात्कार करने के आरोप में 35 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इस मामले ने एक बार फिर मुंबई को शर्मिंदा कर दिया है। घटना के अनुसार मानखुर्द थाना क्षेत्र के रहवासी 35 वर्षीय दरिंदे ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक छह साल की बच्ची का बलात्कार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस दरिंदे ने बच्ची को

टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गया और वहां उसका बलात्कार किया किया। बाद में बच्ची ने घर जाकर अपनी मां से इसकी शिकायत की, जिसने तुरंत ही मानखुर्द थाने में तक्रर दर्ज करवाई। वहीं इस आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और POCSE अधिनियम के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बीते 23 जनवरी को मुंबई के वर्ली थाना क्षेत्र में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को 20 महीने की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ वकड की धारा 376 और POCSE एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का पार्टी ऑफिस गिराने के खिलाफ प्रदर्शन पालघर में हादसे में चार की मौत



मुंबई : शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय को गिराए जाने के विरोध में मंगलवार को बांद्रा में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता पश्चिमी मुंबई में पार्टी एमएलसी अनिल परब के कार्यालय को गिराए जाने का विरोध कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि उद्धव ठाकरे खेमे के पूर्व मंत्री परब भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व

वाली सरकार के खिलाफ उनके कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय के बाहर तैनात किए थे। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सोमवार को दावा किया था कि बांद्रा में परब के ह्यअवैध ऑफिस को तोड़ दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि परब बांद्रा पूर्व में MHADA कॉलोनी में एक हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में ऑफिस चला रहे थे। जिसे सोसाइटी द्वारा हाल ही में समाज गिरा दिया गया था।

पनवेल में लिफ्ट देने के बहाने 20 साल की युवती से किया बलात्कार...

एक आरोपी गिरफ्तार तो दूसरा फरार



नवी मुंबई : नवी मुंबई के पड़ोसी शहर पनवेल में ऑटोरिक्शा में लिफ्ट देने के बहाने महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा फरार है। पुलिस के मुताबिक पनवेल में रविवार देर रात एक 20 वर्षीय महिला के साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला नवी मुंबई के खोपोली से काम के सिलसिले में पनवेल आई थी। रात करीब 2 बजे महिला के साथ ये घटना हुई।

5 मिनट में उड़ा लेते थे बुलेट बाइक बंटी-बबली को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोरीवली : बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट चोर बंटी-बबली को गिरफ्तार किया है। जो केवल बुलेट बाइक की ही चोरी किया करते थे। नवंबर से जनवरी महीने के बीच इन बुलेट चोरों ने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद से 3 बुलेट की चोरी की। चौथी बुलेट के चोरी से पहले कस्तूरबा पुलिस ने इन चोरों को रीगाथ गिरफ्तार कर लिया। इन बुलेट चोर-बंटी बबली के पास से 3 बुलेट बाइक बरामद की गई हैं। चोरों ने इन्हें चोरी करने के बाद नासिक के ओझर गांव में 25 हजार रुपये में बेच दिया था। कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट खरीदार को भी गिरफ्तार किया है जो बिना पेपर के बुलेट बाइक खरीदता था। कस्तूरबा



पुलिस स्टेशन से बुलेट बाइक चोरी की वारदात में पुलिस को सीसीटीवी में चोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए ट्रैप लगाकर बंटी और बबली को चौथे बुलेट चोरी से पहले गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर बुलेट चोर महेश भालचंद्र खापरे उम्र 27 वर्ष जो मुराबाड़ ठाणे का रहने वाला है। इसके

ऊपर वाशिंद, इगतपुरी और बदलापुर में 5 बाइक चोरी के केस दर्ज हैं।

15 महीने जेल में रहकर आया था आरोपी

पुलिस का कहना है कि आरोपी 15 महीने जेल में रहकर आया था। ये इतना शातिर है कि बुलेट चुराने में केवल 5 मिनट लगता है। कस्तूरबा पुलिस ने आरोपी साकिनाबानो मोहम्मद अनीस गोसी (22) और बाइक खरीदार ललित किसन पवार (19) को भी गिरफ्तार किया है। बुलेट चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए लड़की को पीछे बैठकर चेकपोस्ट पार किया करता था। वह सकीनाबानो के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए बुलेट की चोरी किया करता था।

दादर में बंदूक की नोक पर घर में घुसकर लूट... एक गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई में इन दिनों अपराध बढ़ता जा रहा है। मुंबई में अपराधी बेखोफ हैं। दादर में बंदूक की नोक पर कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं कुछ स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश भी है।

मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के दादर वेस्ट इलाके में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर एक घर में लूटपाट की। मिठाई देने के बहाने



घर में घुसे थे। और फिर बंदूक की नोक पर घर में लूटपाट की। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा फरार। फरार आरोपी की तलाश जारी है। इस मामले में आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। एक और मामले में मुंबई मानखुर्द थाना क्षेत्र के रहवासी 35 वर्षीय 'दरिंदे' ने अपने

ही पड़ोस में रहने वाली एक छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस दरिंदे ने बच्ची को 'टॉफी' का लालच देकर अपने घर ले गया और वहां उसका बलात्कार किया किया। बाद में बच्ची ने घर जाकर अपनी मां से इसकी शिकायत की, जिसने तुरंत ही मानखुर्द थाने में तक्रर दर्ज करवाई।



संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

असीमित नहीं अधिकार

वैसे यह पहली बार नहीं है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये किया हो। तमाम सरकारों के दौरान ऐसा होता रहा है, लेकिन राजग सरकार के दौरान इसकी आवृत्ति बढ़ी है। विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट की यह नसीहत तार्किक व मार्गदर्शक है कि कानून उसे यह हक नहीं देता कि वह मनमाने ढंग से किसी की प्रतिष्ठा से खेले, उन्हें परेशान करे या किसी तरह का दबाव बनाये। अदालत ने साफ कर दिया कि उसे सिर्फ और सिर्फ धनशोधन के मामले में ही कार्रवाई करने का कानूनी हक है। वह महज अनुमान के आधार पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकती। यदि ऐसा कोई प्रयास होता है तो कानून के दायरे में ही उसकी सुनवाई होनी चाहिए। दरअसल, हाईकोर्ट ने ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई की थी जिसमें धनशोधन की स्पष्ट स्थिति न होते हुए भी ईडी ने कार्रवाई की थी। आरोप लगते रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने कई मामलों में विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर वाले मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। यही वजह है कि ईडी की दखल के बावजूद कोई धनशोधन का मामला उजागर नहीं हो सका। महज इस शक पर कि आय से अधिक की संपत्ति वाले मामले में धनशोधन का एंगल भी हो सकता है। कोर्ट का मानना है कि अन्य विभाग की जांच में यदि धनशोधन का मामला उजागर होता है तो ईडी दखल दे सकती है।

गाहे-बगाहे ईडी की कारगुजारियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यह मामला विगत में शीर्ष अदालत के पास भी पहुंचा था। तब भी कोर्ट ने उसके गिरफ्तारी व जब्ती के अधिकार को तो माना था लेकिन साथ ही नसीहत भी दी थी कि उसे अपने दायरे में रहकर ही काम करना होगा। ऐसे में उम्मीद जगी है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ईडी संयम के साथ काम करेगा। दरअसल, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं, उनके निशाने पर विपक्षी सरकारों वाले राज्यों के नेता रहे हैं। अब चाहे आयकर विभाग हो, सीबीआई हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय, विपक्षी पार्टियां उनके निशाने पर रही हैं। इन पर राजनीतिक दुराग्रह के चलते कार्रवाई करने तथा सत्तारूढ़ दल के नेताओं को अभयदान देने की बात कही जाती रही है। बहरहाल, हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद वे तमाम लोग राहत की सांस लेंगे, जिनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से कार्रवाई हुई और वे कार्यवाही के अंतहीन त्रास को झेल रहे हैं। मामले में तमाम सफाई देने के बावजूद उनके मामलों का पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है। वहीं जांच एजेंसी को नसीहत दी गई है कि जांच के बाद तथ्य पाये जाने के बाद ही किसी के खिलाफ छापे की कार्रवाई हो तथा कानूनी रूप से अधिकृत प्राधिकारों के माध्यम से ही मामले की सुनवाई की जानी चाहिए। उसके पास यह जांच करने का अधिकार नहीं है कि कहीं इस तरह का आर्थिक अपराध हुआ है।

✉ editor@rokhoklekhani.com

🐦 Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

महाराष्ट्र में खसरे का संक्रमण

टास्क फोर्स ने जताई चिंता, ७२ फीसदी शिशुओं की हुई मौत

मुंबई : महाराष्ट्र में ढाई महीने पहले से शुरू हुए खसरे का संक्रमण अभी टला नहीं है। खसरे की रोकथाम को लेकर 'ईडी' सरकार कोई उचित इंतजाम नहीं कर रही है। 'ईडी' सरकार की इस लापरवाही को लेकर टास्क फोर्स ने भी चिंता जताई है। राज्य के खसरा टास्क फोर्स ने चिंता जताते हुए कहा है कि बीमारी का संकट अभी टला नहीं है। साथ ही यह भी आशंका व्यक्त की है कि आनेवाले समय में खसरे के संक्रमण में वृद्धि होगी, इसलिए बीमारी की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। टास्क फोर्स के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि नौ माह से कम उम्र के बच्चों को खसरे के टीके की अतिरिक्त खुराक देने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। इसे लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार को पत्र भी दिया जाएगा।



राज्य में खसरे से प्रभावित हुए नौ महीने से कम उम्र के ७२ फीसदी शिशुओं की मौत हुई है, जो कि बड़ी ही चिंता की बात है। मनपा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक साल २०२० और २०२१ में कोविड के कारण दूसरी बीमारियों के वैक्सिनेशन का काम प्रभावित हुआ था, जिसमें खसरा भी शामिल है। इस वजह से बड़ी संख्या में बच्चे खसरे की वैक्सिन लेने से चूक गए। बीते साल सितंबर के आखिर से ही खसरे के मामलों में तेजी आई। मुंबई

सफाई व पोषण की कमी, कमजोर इम्युनिटी, वैक्सिन नहीं लगवाने जैसी वजहें खसरे की बीमारी के फैलने का मुख्य कारण है। बताया गया है कि राज्य में खसरे का प्रकोप मार्च माह तक जारी रहने की आशंका है। हालांकि, राज्य का स्वास्थ्य विभाग भले ही खसरे के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक सक्रिय रणनीति बनाने की योजना बना रहा है। इसके अनुसार जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अब तक खसरे के संक्रमण को पैठलने से रोकने के लिए किए गए सारे नीतिगत उपाय खामियों के चलते विफल साबित हुए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार का यह प्रयास भी खासा कारगर नहीं होनेवाला है। खसरा परिक्षण लैब स्थापित करने में 'ईडी' सरकार रुचि भी नहीं दिखा रही है।

आवारा कुत्तों की दहशत



मुंबई : मुंबई में आवारा कुत्तों की दहशत इस कदर बढ़ गई है कि इनके आतंक से मुंबईकर खौफ में जी रहे हैं। मनपा आवारा कुत्तों के उपद्रव को रोकने के लिए कई उपाय कर रही है, बावजूद इसके कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। यही कारण है कि रोजाना लगभग १५० से अधिक मुंबईकर खूंखार कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। पिछले दो वर्षों में १,१२,७६९ लोगों को कुत्तों ने काटा है। फिलहाल, मनपा के सामने आवारा कुत्तों के खतरे को खत्म करने की चुनौती पैदा हो गई है। आवारा कुत्तों के उपद्रव को रोकने के लिए मनपा द्वारा नसबंदी किए जाने के साथ ही रेबीज के इंजेक्शन लगाने जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बाद भी आवारा कुत्तों का आतंक कायम है। खासतौर पर रात के समय शांत मुद्रा में बैठे ये आवारा कुत्ते राहगीरों पर अचानक झपट्टा मारकर उन्हें काट लेते हैं। ऐसे में काम पर से देर रात घर लौटने वाले कर्मचारियों में काफी डर है। साल २०१४ में जब मनपा ने मुंबई में कुत्तों की गणना की थी तो

यहां इनकी संख्या २,९६,२२१ थी। बताया गया है कि नसबंदी न होने पर मादा कम से कम चार बच्चों को जन्म देती है, इसलिए मुंबई में कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय के निर्देशानुसार और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मनपा द्वारा प्रति वर्ष ३० फीसदी कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। मुंबई में आवारा कुत्तों के उपद्रव को रोकने के लिए साल २०१४ से दिसंबर २०२२ तक ३,८८,४२९ कुत्तों की नसबंदी की गई। आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए कुत्तों को पकड़ने के लिए मनपा ने चार 'डॉग वैन' खरीदी हैं। मॉनिटरिंग समिति द्वारा नसबंदी पर निगरानी रहती है। ये चार डॉग वैन मुलुंड, मालाड, महालक्ष्मी और बांद्रा में तैनात हैं। जख्मी कुत्तों को पकड़कर देवनार के पशु अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अधिकारी ने बताया कि सात दिनों तक जांच के बाद अगर स्थिति स्थिर रहती है तो उन्हें वापस उस स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उन्हें लाया हुआ रहता है।

**सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बीमार !
उचित उपचार की कमी, डॉक्टरों की सीमित उपलब्धता...**



पालघर : गरीब और पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ही एकमात्र सहाय होती हैं लेकिन जब ये स्वास्थ्य सेवाएं ही बीमार पड़ जाते तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां इलाज करानेवाले मरीजों का क्या हाल होता होगा? हम बात कर रहे हैं पालघर के ग्रामीण अस्पतालों की, जहां की स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय से सुविधाओं की कमी के चलते अस्वस्थ चल रही हैं। बता दें कि पालघर के ग्रामीण अस्पतालों की व्यवस्था ऐसी है कि यहां पर मरीजों को सही समय पर एंबुलेंस न मिलने, उचित उपचार की कमी, डॉक्टरों की सीमित उपलब्धता कई और कारणों के चलते अब तक कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी जिले की स्थापना के ८ सालों के बाद भी पालघर जिले के सरकारी अस्पताल बीमार चल रहे हैं। समाजसेवी कृष्णा दुबे ने 'दोपहर का सामना' संवाददाता को बताया

कि यहां पर आदिवासी बाहुल्य कई गांव हैं। प्रत्येक गांव की आबादी हजारों के करीब है परंतु हजारों की आबादी वाले गांवों में मुश्किल से मात्र एक-एक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य सदी, बुखार का इलाज तो मिल जाता है लेकिन आज के समय की सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की यहां कोई व्यवस्था नहीं है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में लंबे समय से कई स्वास्थ्य कर्मियों के पद भी खाली हैं। ऐसे में इलाज के लिए मरीजों को गुजरात, सिलवासा और मुंबई, ठाणे, नासिक के अस्पतालों में दर-दर भटकना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रसव के लिए महिलाओं को तारीख नजदीक आने पर अस्पताल के आस-पास किसी परिजन के घर रहना पड़ता है, ताकि समय पर इलाज मिल सके। पालघर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों से लगाया जा सकता है।

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की सीबीआई जांच पूरी

पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को यह बताने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है कि क्या नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की जांच पूरी हो गई है। दरअसल कोर्ट का यह निर्देश तब आया जब सीबीआई द्वारा कोर्ट में दलील दी गई कि सामाजिक कार्यकर्ता और तर्कवादी दाभोलकर की हत्या की जांच कर रहे अधिकारी इस मामले को बंद करने की सिफारिश कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने 2013 में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच पूरी कर ली है और जांच अधिकारी ने सक्षम अधिकारी को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल दाभोलकर के परिवार का आरोप है की इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है। इस संबंध में दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है।



प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कोर्ट के समक्ष दावा किया कि सीबीआई ने समुचित ढंग से पूरे मामले की जांच नहीं की है। जांच में अब भी कई खामियां हैं जिनकी जांच किया जाना बाकी है। याचिका में भी मुक्ता दाभोलकर ने हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की निगरानी जारी रखने का अनुरोध किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सीबीआई से मामले में उसकी जांच की स्थिति बताने को कहा था। सीबीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की

खंडपीठ को सोमवार को बताया कि एजेंसी ने मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है। सिंह ने कोर्ट को बताया, हजहां तक सीबीआई का संबंध है, जांच की गई और अब वह पूरी हो चुकी है...32 गवाहों में से 15 से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। अब तक इस मामले में सीबीआई ने पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। सीबीआई का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के जांच अधिकारी ने मामले को बंद करने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट दायर की है।

जिस पर अंतिम फैसला एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट पर फैसले के लिये कोर्ट से तीन हफ्तों का समय मांगा। जिसे हाईकोर्ट स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख तीन हफते बाद की दी है। बता दें कि कार्यकर्ता केतन तिरोडकर और फिर दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर की याचिका पर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच की कमान पुणे पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी। तब से ही हाईकोर्ट इस मामले की जांच की प्रगति की निगरानी भी कर रहा है। महाराष्ट्र अधिश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर के दौरान पुणे के ओकरेश्वर पुल पर दो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का खूब विरोध हुआ था और सूबे का राजनीतिक पारा भी चढ़ा था।

गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन मामले में पुलिस ने वापस लिया मुकदमा, 36 लोग बनाए गए थे आरोपी

मुंबई : मुंबई पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। यह प्रदर्शन जनवरी, 2020 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (खटव) में छात्रों पर हुए हमले के विरोध में किया गया था। सोमवार को मुंबई की एक अदालत ने मुंबई पुलिस की मुकदमा वापसी की याचिका को मंजूरी दे दी। पुलिस ने अपनी दलील में कहा है कि आरोपियों ने बिना किसी व्यक्तिगत हित या लाभ के कथित कृत्य को अंजाम दिया था। बता दें, मजिस्ट्रेट एस वी डिंडोकर ने इस महीने की शुरुआत में मामले को वापस लेने के आवेदन को स्वीकार कर लिया था। सोमवार को आदेश उपलब्ध कराया गया।

प्रदर्शन में कोई जनहानि नहीं हुई
पुलिस ने इस मामले को खत्म



करते हुए कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के साथ-साथ कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें, मामले की जांच कर रही कोलाबा पुलिस ने दिसंबर 2020 में 36 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि जेएनयू में हिंसा की खबरें देर शाम सामने आने के बाद लोग पांच जनवरी, 2020 की आधी रात को गेटवे ऑफ इंडिया पर मोमबत्तियां लेकर इकट्ठा होने लगे थे। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 400 हो गई थी।

महारेरा के रडार पर लापरवाह बिल्डर, 19,539 बिल्डरों को भेजा नोटिस



मुंबई : घर खरीदारों के लेन-देन को विश्वसनीय बनाने के लिए महारेरा ने विभिन्न उपाय योजना बनानी शुरू की है। महारेरा ने मई 2017 से मार्च 2022 तक पंजीकृत परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। जिन बिल्डरों ने रेरा अधिनियम की धारा 11 के तहत जानकारी को अद्यतित नहीं किया है ऐसे 19 हजार 539 परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.. महारेरा की ओर से जानकारी दी गई की इनमें से मात्र 67 परियोजनाओं से जानकारी प्राप्त हुई है। वेबसाइट पर इस तरह से जानकारी अपडेट नहीं करने पर प्रमोटरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

बता दे कि महारेरा की नोटिस का जवाब नहीं देने वाले विकासकर्ताओं को गड़बड़ी सुधारने के नोटिस सी गई है उन्हें नोटिस की तारीख से 30 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद भी जवाब या त्रुटि सुधार नहीं मिलने पर महारेरा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जुर्माने की यह राशि उन्हें अपनी 30 फीसदी राशि में से देनी होगी. रेरा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, महारेरा के साथ एक आवास परियोजना को पंजीकृत करने के बाद, परियोजना विकासकर्ता को पंजीकरण के समय प्रदान की गई जानकारी को हर 3 महीने में महारेरा की वेबसाइट पर अपडेट करना आवश्यक है. ग्राहक को समय-समय पर परियोजना की वर्तमान स्थिति जानने की जरूरत है. हालांकि, यह देखा गया है कि अधिकांश परियोजनाओं ने पंजीकरण के बाद से इस जानकारी को अपडेट नहीं किया है इसलिए महारेरा ने कार्रवाई शुरू की है.

सांप या बिच्छू के काटने पर सभी लोगों के लिए आर्थिक सहायता की मांग, याचिका पर HC ने क्या कहा?

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा. कोर्ट ने इसके साथ ही सांप या बिच्छू के काटने पर किसानों ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मारने की खंडपीठ ने कहा कि अदालत राज्य सरकार को किसी विशेष योजना को एक विशिष्ट तरीके से तैयार करने का निर्देश नहीं देगी. अदालत ठाणे स्थित निसर्ग विज्ञान संस्था नाम के एक एनजीओ की ओर से दायर एक



दो लाख रुपये तक के मुआवजे के पात्र हैं. सांपों का बचाव कार्य में शामिल इस एनजीओ याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि बचाव प्रक्रिया के दौरान उसके अपने ही कुछ सदस्यों को सांपों ने काट लिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनुराग कुलकर्णी ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक योजना थी जिसमें सांप या बिच्छू के काटने वाले किसी भी व्यक्ति को कवर किया गया था. कुलकर्णी ने यह भी कहा कि ऐसे कई मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं लेकिन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास राजस्व रिकॉर्ड में दशराने के लिए जमीन नहीं है.

मध्य प्रदेश की योजना का दिया गया हवाला
योजना के अनुसार, जिन किसानों का नाम राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, वे सांप और बिच्छू के काटने के मामलों में हुई चोट के आधार पर

नवी मुंबई देश का सर्वोच्च 'वाटर प्लस' रेटिंग वाला शहर

नवी मुंबई : राज्य सरकार के 'माझी वसुंधरा अभियान' में भी नवी मुंबई को राज्य के नंबर वन इको फ्रेंडली शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, नवी मुंबई ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च की ओर से लगातार आठ वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ वित्तीय क्रेडिट रेटिंग 'इंडिया डबल ए प्लस स्टेबल' को बनाए रखा है। संत गाडगे बाबा शहरी स्वच्छता मिशन महाराष्ट्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और नवी मुंबई शहर पिछले कई वर्षों से राज्य में हमेशा स्वच्छता में प्रथम स्थान पर रहा है।

मनपा ने कुल बजट का अब तक मात्र 37 प्रतिशत पैसा ही किया खर्च

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली और सबसे धनी मुंबई महानगर पालिका ने इस साल अभी तक मंजूर बजट का दिसंबर आखिरी तक मात्र 37 प्रतिशत ही पैसा खर्च कर पाई है। मनपा ने वर्ष 2022-23 में मूलभूत परियोजनाओं और लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए कुल 22646 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था जिसमें से मनपा दिसंबर आखिरी तक 8398 करोड़ का ही खर्च कर पाई है। जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान विकास योजनाओं के लिए तय राशि में से मनपा ने 40 प्रतिशत से अधिक खर्च किया था। वर्ष 2020-21 में विकास कार्यों



और डेवलपमेंट प्लान पर खर्च करने में फिसट्टी साबित हुई है। मनपा बजट में प्रस्तावित निधि का 31 मार्च 2023 तक इस्तेमाल कर सकती है।

मार्च 2019 से कोरोना जैसी महामारी का सामना करने वाली मनपा ने वर्ष 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य के लिए 2510 करोड़ का प्रावधान किया था जिसमें मात्र 485 करोड़ रुपये खर्च कर सकी है मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल बजट पेश करते समय मुंबई में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति पर विशेष जोर देने का दावा किया था। मनपा ने एसटीपी के 7 प्लांट लगाने की घोषणा की है।



ठाणे में 20 वर्षीय युवक की हत्या, छह लोग गिरफ्तार



ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुरानी रजिश को लेकर 20 वर्षीय युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आकाश कुमार राज पर सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे हमला हुआ था। घटना से कुछ ही समय पहले राज का मीरा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर चार लोगों के साथ विवाद हुआ था। अधिकारी ने कहा कि राज पेट्रोल पंप से एक गैराज की ओर चला गया लेकिन अन्य लोगों के साथ मिलकर इन चारों ने राज का पीछा किया और उस पर धारदार हथियार एवं लोहे की छड़ से हमला किया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य सूचनाओं का इस्तेमाल किया।

अनिल देशमुख ने DCM देवेन्द्र फडणवीस को लिखा पत्र



महाराष्ट्र : हमेशा चर्चा में रहे अनिल देशमुख को लेकर एक खबर सामने आई है। दरअसल नागपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक ने नागपुर जिले में किसानों से बकाया ऋण की वसूली के लिए किसानों की कृषि भूमि की नीलामी की है। लेकिन किसानों की हालत खराब होने के कारण वे कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। इसलिए

पूर्व गृह मंत्री और विधायक अनिल देशमुख ने उपमुख्यमंत्री और नागपुर के पालक मंत्री देवेन्द्र फडणवीस से नीलामी प्रक्रिया को स्थगित करने का अनुरोध किया है।

किसानों को बदनाम किया
जिन किसानों का कर्ज बकाया है और जिनके खेत नीलाम हो रहे हैं, उनकी सूची बैनर के बीच में लगाई

अनिल देशमुख ने पत्र लिख की मांग...!

ज्ञात हो कि इस साल भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता बहुत कम है। दूसरी ओर नागपुर जिले में भारी बारिश के कारण संतरों और आमों को भारी नुकसान होने के बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा बंजर होने के कारण सोयाबीन और कपास की फसल को बाजार में उचित दाम नहीं मिल पा रहा है।

नीलामी स्थगित करने का अनुरोध

नतीजतन, किसान नागपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिए गए कर्ज को चुका नहीं पाए। लेकिन अब जब बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए सीधे किसानों के खेत नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की है तो इससे किसानों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इसी के चलते अनिल देशमुख ने देवेन्द्र फडणवीस से पत्र के माध्यम से नागपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में बकाया ऋणों को लेकर चल रही नीलामी की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया है।

गई है। इससे आर्थिक तंगी से परेशान किसान बदनाम हो रहे हैं। अनिल देशमुख ने भी अपने पत्र में इस गंभीर मामले का जिक्र किया है, इस तरह वे अब जेल से बाहर आने के बाद एक्टिव हो गए हैं।

शिंदे सरकार ने रेलवे परियोजनाओं का 50% खर्च न उठाने के MVA सरकार के फैसले को पलटा....



मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रेलवे परियोजनाओं का 50 प्रतिशत खर्च न उठाने के पूर्ववर्ती एमवीए सरकार के फैसले को पलट दिया है और सांसदों से विभिन्न लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। सोमवार को यहां महाराष्ट्र के लोकसभा सांसदों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आम आदमी के लिए लाभकारी कई परियोजनाएं केंद्र सरकार के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने कहा, "हमें उनमें तेजी लाने तथा उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बैठक में विपक्ष के कुछ सांसद अनुपस्थित रहे। शिंदे ने यह भी कहा कि सांसदों से मिली प्रतिक्रिया पर गौर किया जाएगा तथा स्थिति का जायजा लेने के लिए दो महीने बाद एक और बैठक होगी। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं में 50 प्रतिशत का योगदान न देने के पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को अब पलट दिया गया है।

मुंबई के डांगरी इलाके में गुटखा तस्करी के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े?

चेहरे पर मुक्का मारा-थूका, क्रू मेंबर्स से मारपीट के बाद उतारे कपड़े!

अबू-धाबी-मुंबई फ्लाइट में हाईवोल्टेज ड्रामा

मुंबई : फ्लाइट्स में एकाएक अनेखी घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बार एयर विस्तारा की अबू धाबी से मुंबई आ रही फ्लाइट में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. इटली की रहने वाली एक महिला ने पहले फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को गाली देना शुरू किया फिर उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं कुछ देर में उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और नग्न अवस्था में ही कॉरिडोर में चलने लगी. चलिए आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ पूरा हंगामा. दरअसल, महिला इकोनॉमी क्लास का टिकट लेकर फ्लाइट पर चढ़ी थी लेकिन बिजनेस क्लास में बैठने की जिद करने लगी. केबिन क्रू ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हंगामा करना शुरू कर दिया. यहां तक की उसने क्रू के साथ मारपीट भी की. पुलिस ने 45 वर्षीय पाओला पेरुशियो नाम की महिला को गिरफ्तार



कर लिया है, जोकि इटली की रहने वाली है.

बिजनेस क्लास में बैठने को लेकर हंगामा

सहार थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें सोमवार (30 जनवरी) को एयर विस्तारा फ्लाइट यूके 256 के केबिन क्रू से शिकायत मिली थी. फ्लाइट ने इसी दिन तड़के 2.03 बजे करळ अबू धाबी से उड़ान भरी थी. उन्होंने बताया कि रात करीब ढाई बजे इकोनॉमी क्लास में बैठी महिला अचानक उठी और दौड़कर क्रू के दो सदस्यों ने पहले महिला से जाकर

बातचीत की. जब उन्हें लगा कि महिला को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो उन्हें उसे उसकी सीट पर वापस जाने को कहा.

क्रू मेंबर के चेहरे पर मारा मुक्का
इतने में ही महिला उन्हें गाली देने लगी और जब उन्होंने महिला से गलत भाषा का इस्तेमाल न करने की बात कही तो महिला ने एक क्रू के चेहरे पर एक मुक्का मार दिया और दूसरे पर थूक दिया. इसके तुरंत बाद जब बाकी क्रू मेंबर्स आए तो महिला ने अपने कपड़े उतारकर फ्लाइट के कॉरिडोर में चलना शुरू कर दिया. काफी देर तक हंगामा चलने के बाद महिला को काबू में किया गया. जब फ्लाइट लगभग 4.53 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी तो महिला यात्री को विस्तारा के सुरक्षा अधिकारियों और फिर सहार पुलिस को सौंप दिया गया.

क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने शुरू की जांच

मुंबई : मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने पिछले सप्ताह डांगरी इलाके में कार्रवाई करके गुटखा तस्करी से संबंधित गैंग को पकड़ा था. सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो यह शक पैदा कर रही हैं कि इस तस्करी के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं. इसी वजह से इस मामले की जांच अब एंटी एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दिया गया है. सोशल सर्विस ब्रांच ने गुरुवार को डांगरी इलाके के उमरखाड़ी और न्यू बंगालीपुरा के कुछ दुकानों पर छपा मारकर वहां से गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जब्त किया था जिसकी कीमत 30 हजार 300 रुपए थी. इस मामले में पुलिस ने अबू सलीम खान, फहीम खान, अबुलश शेख, शारिक अझीम खान, मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद फरहान अब्दुल बटाटेवाला और अझीम



इस्माईल खान को गिरफ्तार किया था. आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को इस तरह के माल के स्टोरेज की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने डांगरी इलाके में स्थित 5-6 दुकानों पर छपा मारा और वहां से करीब 45 लाख रुपए कीमत का गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जब्त किया. इस गोदाम के मालिक अबू सलीम खान और अझीम इस्माईल खान से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग कई साल से इस धंधे में हैं और सरकार के गुटखा बैन करने की वजह से इनके व्यापार में बहुत फायदा होता है, इसी वजह से ये लोग गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक

बड़ी मछलियां हैं विदेश में...

इस मामले में पुलिस ने क्लउ की धारा 328, 273, 199 के तहत मामला दर्ज किया है, जांच में यह भी पता चला कि गिरफ्तार आरोपी तो छोटे मोटे काम के लिए यहां थे, लेकिन इस गैंग की बड़ी मछलियां विदेश में हैं. सूत्रों ने बताया कि पुलिस को शक है कि इस गुटखा तस्करी गैंग के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हैं. इस मामले के मुख्य आरोपी अबू खान के खिलाफ गुटखा तस्करी से जुड़े 18 मामले दर्ज हैं.

से गुटखा लाते थे. आसिफ माझगाव, सनी ठाकुर, वकार भिवंडीवाला थोक के भाव में गुटखा सप्लाइ करते थे.